

केशवानंद भारती नरिणय के 50 वर्ष

24/04/2023 '50 years of Kesavananda Bharati judgment' 2023

संदर्भ

संवधान के 'मूल ढाँचे' की अवधारणा का उद्भव 50 वर्ष पूर्व [केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य](#) (1973) वाद के ऐतिहासिक नरिणय में हुआ था।

मूल ढाँचे का सदिधांत एक अत्यधिक विवादास्पद बहुलवादी न्यायिक रचना है जिसे सरकार की सभी शाखाओं और भारत के नागरिकों द्वारा स्वीकार किया गया है।

केशवानंद भारती वाद ने असीमति संसदीय संप्रभुता पर अंकुश लगाया और संवधान की मूल पहचान को मान्यता देकर एक नया व्याख्यात्मक उद्यम शुरू किया, जिसे किसी भी संवधान संशोधन से नष्ट नहीं किया जा सकता है।

आज मूल ढाँचे का सदिधांत संवधानिक [न्यायिक समीक्षा](#) का एक लगातार विकास करता पहलू बन गया है।

क्या था केशवानंद भारती वाद?

■ केशवानंद भारती वाद (1973):

- इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने [गोलकनाथ वाद](#) में दिये गए अपने नरिणय के विरुद्ध नरिणय दिया। इसने 24वें संशोधन अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा और कहा कि संसद के पास किसी भी मूल अधिकार को कम करने या आहरति करने का अधिकार है।
- इसके साथ ही, इसने संवधान का 'मूल ढाँचा' या 'मूल विशेषताओं' का एक नया सदिधांत प्रस्तुत किया।
- इसने नरिणय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संवधानिक शक्ति इसे संवधान के 'मूल ढाँचे' में हस्तक्षेप करने या इसे बदलने में सक्षम नहीं बनाती है।
- इसका अभिप्राय यह है कि संसद किसी ऐसे मूल अधिकार को कम नहीं कर सकती या आहरति नहीं कर सकती जो संवधान के 'मूल ढाँचे' का अंग है।

मूल ढाँचे के सदिधांत की पृष्ठभूमि में प्रमुख वाद

■ शंकर प्रसाद नरिणय 1951:

- आरंभ में न्यायापालिका का विचार था कि संसद की संवधान संशोधन शक्ति अप्रतिबंधित है क्योंकि यह संवधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, यहाँ तक कि यह अनुच्छेद 368 में भी संशोधन कर सकती है जो वस्तुतः संसद को संशोधनकारी शक्ति प्रदान करता है।

■ गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य 1967:

- सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की शक्तियों के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाया कि वह संवधान के भाग III, अर्थात् मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती और इस प्रकार मूल अधिकारों को एक 'उत्तमोत्तम स्थिति' (Transcendental Position) प्रदान की।

■ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973:

- इसमें एक ऐतिहासिक नरिणय दिया कि संसद संवधान के मूल ढाँचे में बदलाव या हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।
- यह माना गया कि यद्यपि संसद के पास संवधान में संशोधन करने की अबाधति शक्ति है, लेकिन यह संवधान के मूल ढाँचे या मौलिक विशेषताओं के साथ छेड़छाड़ या उसे कमजोर नहीं कर सकती है क्योंकि इसमें केवल संवधान संशोधन की शक्ति निहित है, न कि संवधान के पुनर्लेखन करने की।

■ इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण वाद:

- इस वाद में, सर्वोच्च न्यायालय ने 39वें संशोधन अधिनियम (1975) के एक उपबंध को अमान्य कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री और लोकसभा

अध्यक्ष से संबद्ध नरिवाचन संबंधी वविादों को सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया था ।

○ न्यायालय के अनुसार, यह उपबंध संसद की संशोधन शक्ति से परे था क्योंकि यह संविधान के मूल ढाँचे को प्रभावित करता था ।

■ मनिर्वा मलिस बनाम भारत संघ:

- मनिर्वा मलिस वाद में, सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय दिया कि "भारतीय संविधान की स्थापना मूल अधिकारों और नदिशक सदिधांतों के बीच संतुलन के आधार पर की गई है ।"
- संसद नदिशक सदिधांतों को लागू करने के लिये मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, यदयिह संशोधन संविधान के मूल ढाँचे को आघात न पहुँचाता हो या उसे नष्ट नहीं करता हो ।

मूल ढाँचे का सदिधांत क्या है?

- केशवानंद भारती वाद में संविधान पीठ ने 7-6 के मत से नरिणय दिया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है यदयिह संविधान के मूल ढाँचे या आवश्यक वशिषताओं में कोई बदलाव या संशोधन को अधिभावी न करे ।
- हालाँकि, न्यायालय ने 'मूल ढाँचे' पद को परिभाषित नहीं किया और केवल कुछ सदिधांतों - जैसे संघवाद, धर्मनरिपेक्षता, लोकतंत्र आदि - को इसके अंग के रूप में सूचीबद्ध किया ।
- तब से "मूल ढाँचे के सदिधांत" को नमिनलिखित वशिषियों को संलग्न करने हेतु व्याख्यायति किया गया है -

- संविधान की सर्वोच्चता,
- वधिा का शासन,
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता,
- शक्तिपृथक्करण का सदिधांत,
- संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य,
- सरकार की संसदीय प्रणाली,
- स्वतंत्र एवं नशिपक्ष नरिवाचन का सदिधांत,
- कल्याणकारी राज्य, आदि ।

- एस.आर. बोमई वाद (1994) मूल ढाँचे के अनुप्रयोग का एक प्रमुख उदाहरण है ।

○ इस वाद में बाबरी मसजिद के वधिंवस के बाद राष्ट्रपति द्वारा भाजपा सरकारों की बरखास्तगी को न्यायालय ने उचित ठहराया, जहाँ इन सरकारों से धर्मनरिपेक्षता के लिये खतरे की बात कही गई ।

मूल ढाँचे के सदिधांत का महत्त्व क्या है?

■ राजनीतिक शक्ति को सीमति करना:

- गोलक नाथ वाद (1967) ने अनुच्छेद 368 की संशोधन शक्ति को मूल अधिकारों की व्यवस्था के अधीन लाकर राजनीतिक शक्ति की सीमा नरिधारित की ।
- मूल ढाँचे ने संविधान की मूल पहचान को चहिनति किया, जिसे किसी भी संशोधन द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है ।
- मूल ढाँचा संविधान के नरिसन को अक्षम बनाता है और यह किसी संविधानिक संशोधन को अधिकृत करती है, न कि संविधानिक तोड़-मरोड़ या वधिटन को ।

■ न्यायिक समीक्षा प्रक्रिया और शक्ति का वविकपूर्ण प्रयोग:

- केशवानंद भारती वाद का उभार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सह-संविधी शक्ति (Co-constituent Power) के वविकपूर्ण प्रयोग के एक अवसर के रूप में हुआ ।
- इसने कार्यपालिका एवं वधिायिका की वृहत पूर्ण शक्तियों को स्पष्ट किया और भय के तर्क को इस मान्यता के साथ खारजि कर दिया कि शक्ति के दुरुपयोग की संभावना इसकी अप्रदत्तता (Non-conferment) के लिये कोई आधार नहीं है ।

■ अंतमि नरिणय का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास:

- न्यायालय मानता है कि मूल सदिधांतों की पहचान करना और उन्हें बनाए रखना उसका उत्तरदायित्व है, जो संविधान की अखंडता को बनाए रखने के लिये महत्त्वपूर्ण है ।
- **NJAC वाद** (2015) में दिया गया नरिणय यह स्पष्ट करता है कि शक्ति का प्रयोग केवल "वधिा के मापदंडों के भीतर, न तो अधिक और न ही कम" किया जा सकता है और संशोधनों की वैधता "वचिरों के आधार पर परीक्षति नहीं की जा सकती है, वे कतिनी भी प्रबलता या वशिद रूप से अभवियक्त हुए हों ।"
- न्यायिक स्वतंत्रता वधिा के शासन के 'सार' (Essence) के रूप में महत्त्वपूर्ण है, जो 'नरिणयात्मक स्वायत्तता' और 'संस्थागत स्वायत्तता' दोनों को शामिल करती है ।

■ संविधानिक परंपराएँ और अभ्यास:

- वधिा के शासन का अर्थ है कि "नरिणयन और वविक के मानदंड" हमेशा संविधान द्वारा परिचालित रहते हैं और 'संविधानिक परंपराओं' के लिये सम्मान की मांग रखते हैं ।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश के अनुसार न्यायिक नयुक्तियों के मामलों में एक परंपरा भारत सरकार अधिनियम, 1935 के समय से ही मौजूद

है।

- 'संवैधानिक परंपराएँ और अभ्यास' लिखित शब्द के साथ अलिखित संविधान के प्रतिलिखन को चिह्नित करते हैं।

संबद्ध मुद्दे

■ स्पष्ट उपबंध नहीं:

- मूल ढाँचे के सिद्धांत का सबसे सामान्य मुद्दा यह है कि संविधान की भाषा में इस सिद्धांत के लिये कोई आधार नहीं है।
- ऐसे किसी उपबंध का अभाव है जो यह निर्धारित कर सकता हो कि संविधान में संशोधन शक्त की क्षमता से परे कोई मूल ढाँचा मौजूद है।

■ शक्तिपृथक्करण के सिद्धांत के वरिद्ध:

- यह सिद्धांत एक त्रिपक्षीय प्रणाली की कल्पना करता है जहाँ शक्तियों को उनके अधिकार क्षेत्र को रेखांकित करते हुए सरकार के तीन अंगों के बीच प्रत्यायोजित एवं वितरित किया जाता है।
- यह शक्ति के पृथक्करण की अवधारणा के साथ असंगत है।

■ विषय-वस्तुगतता या 'सब्जेक्टिवि मैटर':

- यह देखा गया है कि मूल ढाँचे के सिद्धांत को अलग-अलग न्यायाधीशों द्वारा उनकी व्यक्तिपरक संतुष्टि के आधार पर अलग-अलग तरीके से परिभाषित किया जाता है।
- यह संवैधानिक संशोधनों की वैधता या अमान्यता को तय करने के निर्णय को न्यायाधीशों की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं से प्रभावित करता है जो तत्समय संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं।

■ निर्वाचित संसद की शक्तियों पर सीमाओं का आरोपण:

- संसद द्वारा अधिनियमित कानून को न्यायालयों द्वारा अमान्य घोषित किया जा सकता है यदि न्यायालय इसे संविधान के मूल ढाँचे के वरिद्ध मान लें।
- इस प्रकार, यह न्यायपालिका को लोकतांत्रिक तरीके से गठित सरकार पर अपना दर्शन थोपने की अनुमति प्रदान करता है।

■ कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं:

- मूल ढाँचे के संघटक तत्व के बारे में निश्चित स्पष्टीकरण की कमी है, जिससे यह सिद्धांत संदिग्ध या अस्पष्ट हो जाता है।
- यह तय करना न्यायालयों के ऊपर है कि मूल ढाँचा क्या है?

■ न्यायिक अतिक्रम की ओर:

- राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को सर्वसम्मति से संसद द्वारा संविधान में संशोधन के रूप में अधिनियमित किया गया था और भारत के 28 में से 20 राज्यों की विधायिका द्वारा इसे पारित किया गया था।
- NJAC विधायक एवं ऐसे कई अन्य मामलों में न्यायालय द्वारा मूल ढाँचे के सिद्धांत के आधार पर हस्तक्षेप किया गया जिन्हें न्यायिक अतिक्रम (Judicial Overreach) की घटनाओं के रूप में देखा गया है।

निष्कर्ष

- मूल ढाँचे के सिद्धांत भारतीय संविधान की आधारशिला है, जो लोकतंत्र के मौलिक सिद्धांतों के संरक्षण और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने में सहायक रहा है। केशवानंद भारती वाद में इसकी प्रस्थापना भारत के लोकतांत्रिक संस्थानों की सशक्तता और प्रत्यास्थता तथा संविधान को बनाए रखने हेतु न्यायपालिका की प्रतिलिखितता का एक वसीयतनामा है।

मूल संरचना का सिद्धांत

Doctrine of Basic Structure

- **मूलविचार** —
 - जर्मनी का संविधान।
- **ऐतिहासिक निर्णय** —
 - के.एस.वन्दे भारतीय मामला, 1973 ('संविधान की मूल संरचना' का अर्थ का पहली बार प्रयोग किया गया था)।
- **मूल संरचना के तन्त्र** —
 - संविधान की सर्वोच्चता, संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान में संशोधन करने की संसद की सीमित शक्ति, अनुच्छेद 32, 136, 141 और 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ, अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालयों की शक्तियाँ ...
- **महत्त्व**
 - संविधान के केंद्रीय आदर्शों को कमजोर करने के लिये एक बहुसंख्यक सरकार की शक्ति को सीमित करता है।
- **आलोचना**
 - "मूल संरचना" का भारतीय संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। इसके अलावा न्यायपालिका द्वारा मूल संरचना की कोई विशेष परिभाषा नहीं दी गई है।
 - मूल संरचना के नाम पर सर्वोच्च न्यायालय ने अत्यधिक शक्ति ग्रहण कर ली है।

क्रमिक विकास

संकीर्ण प्रसाद मामला (1951) और सज्जन सिंह मामला (1965)	सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति संसद के पास है।
गोल्डक नाथ बनाम पंजाब राज्य, 1967	संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है और यह शक्ति केवल एक संविधान सभा के पास है; 24वाँ संशोधन अधिनियम, 1971 पेश किया गया।
के.एस.वन्दे भारतीय बनाम केरल राज्य, 1973	संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन यह संविधान के मूल ढाँचे या आवश्यक विशेषताओं को नहीं बदल सकती है।
इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण, 1975	अपारंपरिक ढाँचे के सिद्धांत की फिर से पुष्टि हुई और 39वाँ संशोधन अधिनियम (1975) के प्रावधान (प्रधानमंत्री और अध्यक्ष से जुड़े चुनावी विवादों को सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखने हुए) को अमान्य कर दिया गया।
मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, 1980	मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बीच न्यायिक पुनर्विलोकन और समन्वय को बुनियादी ढाँचे में जोड़ा गया।
वामन राव बनाम भारत संघ, 1981 मामला	सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सिद्धांत के.एस.वन्दे भारतीय में निर्णय की तारीख के बाद लागू किये गए संवैधानिक संशोधनों पर लागू होगा।
इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला, 1992	विधि के शसन को बुनियादी ढाँचे का एक हिस्सा घोषित किया गया।
एस.आर बोम्बेई बनाम भारत संघ, 1994	संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, राष्ट्र की एकता और अखंडता और सामाजिक न्याय को संविधान की अपारंपरिक संरचना के रूप में दोहराया गया।

अभ्यास प्रश्न: भारत के संवैधानिक न्यायशास्त्र में मूल ढाँचे के सिद्धांत के महत्त्व और विकास की चर्चा करें। इसने शक्तिपृथक्करण के सिद्धांत को और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा विधि के शासन को बनाए रखने में न्यायपालिका की भूमिका को कैसे प्रभावित किया है?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

????????

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन के परे कर दिया।
2. भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: (b)

??????

प्र. "संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति एक परसीमति शक्ति है और इसे आत्यंतिक शक्त के रूप में वसित नहीं किया जा सकता है।" इस कथन के आलोक में व्याख्या कीजिये कि क्या संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपनी शक्ति का वशिदीकरण करके संविधान के मूल ढाँचे को नष्ट कर सकती है? (2019)

